

Title: Requested the Government to grant citizenship to the Pakistani immigrants in the State of jammu and Kashmir who have been staying there since time of the Partition..

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देश के विभाजन के समय लाखों लोग पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवेश कर गए, लेकिन दुख इस बात का है कि आज 53 साल बीत जाने के बाद भी उन लोगों को शहरी हुकूम नहीं मिले हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ ऐसा कोई कानून हो कि 53 साल तक वहाँ रहने के बाद उनको उस देश के शहरी हुकूम नहीं मिलें।

महोदय, इंग्लैंड, यू.एस.ए., जर्मन या फ्रांस किसी भी देश को देख लीजिए, वहाँ तीन-चार साल रहने के बाद उस देश की नागरिकता उनको मिल जाती है, लेकिन हमारे देश में हमारे ही देश के नागरिकों को 53 साल बीत जाने के बाद भी शहरी हुकूम नहीं दिए गए हैं जिसके कारण उनकी दुर्दशा हो रही है। आज स्थिति यह है कि वे वोट नहीं डाल सकते हैं। जो इस देश को अपनी मातृभूमि समझकर इस देश में आए और जम्मू तथा कश्मीर स्टेट में बसे, उन्हें उनके शहरी हुकूम से वंचित रखा गया है। वे वोट नहीं डाल सकते, चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकते हैं।

महोदय, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ इतने वॉ तक रहने के उपरान्त भी लोगों को

*Not Recorded.

उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया हो। हम ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, लेकिन उनके हुकूम को न देकर हम ह्यूमन राइट कमीशन का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 53 वॉ से आज तक उनको शहरी हुकूम क्यों नहीं दिए गए ? उनकी तीन पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई हैं। उनको सिर छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित किया गया है। वे जमीन नहीं खरीद सकते हैं, घर नहीं बना सकते हैं, स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वहाँ की सरकार उनको नागरिक हुकूम नहीं दे रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि उनको शहरी हुकूम दिए जाएँ। (ब्यवधान)

MR. SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions) *â€